सुविधा : गांवों में आधारभूत संरचना के विकास पर जोर, 1600 पुल-पुलियों के निर्माण को भी मिली मंजूरी

बिहार में 26 हजार किमी ग्रामीण सड़कें बनेंगी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। प्रदेश में 26 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। इसके अलावा 1600 नये पुल-पुलियों का भी निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को इसकी घोषणा की। वे विभागीय सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के पहले इनका निर्माण कर लिया जाएगा। अर्थात नवंबर 2025 के पहले सड़क और पुल-पुलिये बन जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। बीते मंगलवार को कैबिनेट ने इसी क्रम में दो अहम फैसले किये। इनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण लड़क उन्नयन योजना को विस्तार देना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को फिर से चालू करने का निर्णय शामिल है। इससे ग्रामीण सड़कों व पुल-पुलियों के निर्माण में न केवल तेजी आएगी बल्कि हजारों बसावटों को संपर्क पथ मिल सकेगा।

600 नये पुल-पुलियों के निर्माण की योजना: ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष तक 10 हजार किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही 13 हजार नयी सड़कों के निर्माण की भी योजना है। इसके अलावा तीन हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण विभिन्न चरणों में है।

इसी तरह एक हजार पुल-पुलियों के निर्माण पर काम चल रहा है जबकि 600 नये पुल-पुलियों के निर्माण की भी योजना है।

संचालन समिति की अनुशंसा पर विभाग देगा मंजूरी: मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए योजनाओं की स्वीकृति जिला संचालन समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा ही की जाएगी। लेकिन, निर्माण की जिम्मेवारी अलग-अलग होगी। इसके अंतर्गत 100 मीटर तक के पुल-पुलियों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग करेगा, जबकि इससे अधिक लंबे पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों विभाग का केवल एक पुल ही गिरा है। एक पुल का सैंटिंग असामाजिक तत्वों द्वारा हटा दिया गया था। वहां निर्माण स्थल को लेकर दो गुटों में विरोध था। इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख भागवत राम और श्रीप्रकाश मौजूद रहे।

10 हजार किमी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा अगले वित्तीय वर्ष तक

- नवंबर 2025 के पहले ये सड़कें और पुल-पुलिये बन जाएंगे
- ग्रामीण सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण में तेजी आएगी : अशोक चौधरी

6823 पुलों को मरम्मत की जरूरत

ग्रामीण कार्य विभाग के 46099 पुल-पुलिया हैं। इनमें 37414 अच्छी स्थिति में हैं, जबकि 6823 पुलों को मरम्मत की जरूरत है। इस पर योजना बनाकर काम किया जा रहा है। शीघ्र ही सारे पुल दुरुस्त होंगे। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनायी जा रही है।

अवसर: 231 सहायक अभियंता नियुक्त होंगे

विभाग में 231 सहायक अभियंता को गेट्स स्कोर पर बहाल किया जाएगा। विभाग में काफी काम बढ़ा है, इसलिए मानव संसाधन को बढ़ाया जाएगा। यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। विभाग में सहायक अभियंता के 883 स्वीकृत पद हैं। इनमें 507 कार्यरत हैं। इस प्रकार 231 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अनुशंसा भेजी गयी है। जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक 231 सहायक अभियंताओं को नियोजन पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी अपनी सहमति दे दी है।

अब पुल-पुलिये और सड़कें एक साथ बनेंगी

अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सड़क बनेंगी, वे बगैर पुल-पुलियों के नहीं होंगी। निर्माण योजना में दोनों को समान रूप से शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पुल-पुलिये बन गए और सड़क नहीं या फिर सड़क बन गए और पुल-पुलिये नहीं। अब इस तरह की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। विभाग को इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं जहां सड़कों का निर्माण किया गया है लेकिन पुल-पुलियों का नहीं। इसी तरह कई ग्रामीण इलाकों में पुल-पुलिये बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है।

65 हजार किमी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत नहीं तो कार्रवाई

- पंद्रह दिनों में निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाएं: मुख्य सचिव
- जहां सड़कें ठीक नहीं, वहां के इंजीनियर-संवेदक नपेंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत (अनुरक्षित) नहीं करने वाले इंजीनियरों-संवेदकों पर कार्रवाई होगी। बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने यह निर्देश दिया। उन्होंने 15 दिनों में पूरे प्रदेश की ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करने और उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

मुख्य सचिव ने पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन लगभग 65 हजार किलोमीटर ग्रामीण पथों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो संवेदक सड़कों के रखरखाव में गड़बड़ी करें, उनके विपत्रों से दंड की राशि की वसूली की जाए और उन्हें काली सूची में डालें।

मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण सड़कों की स्वतंत्र जांच के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को उक्त पथों की सूची उपलब्ध कराएं। अपने स्तर से प्रत्येक बुधवार या गुरुवार को अभियान चला कर बीआरआरएमएस मोबाइल एप से अन्य विभागों के अभियंताओं से जांच कराकर फीडबैक प्राप्त करने को कहा जाए।

दो वर्षों में सभी छूटे टोलों तक सड़क पहुंचेगी

मुख्य सचिव ने छूटे टोलों को दो वर्षों में संपर्क सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 4200 छूटे टोले व बसावटों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही सभी क्षतिग्रस्त ग्रामीण पथों के नवीनीकरण व उन्नयन के लिए चरणबद्ध तरीकों से चयन कर निर्माण की स्वीकृति दें।

70 साल से अधिक उम्र वालों को पांच लाख रुपये का मुफ्त इलाज

आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी, परिवार में 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को संयुक्त रूप से मिलेगा लाभ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को पांच लाख रुपये सालाना तक मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से छह करोड़ बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। मांग आधारित इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण करना होगा। इसकी पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत किसी भी आयवर्ग के 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी चरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का कवरेज मिलेगा। जिन परिवारों को पहले से आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जा रहा है, उनमें भी 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अलग से पांच लाख रुपये सालाना का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यानी ऐसे परिवारों को जिन्हें पहले से आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें अब कुल 10 लाख तक का कवर मिलेगा। यदि किसी परिवार में दो बुजुर्ग हैं तो दोनों के बीच संयुक्त रूप से यह सुविधा होगी।

ध्यान देने की बात है कि मोदी सरकार ने 2017 में देश भर के 10.74 करोड़ गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच लाख रुपये सालाना मुफ्त और कैशलेश इलाज के लिए कवर किया गया था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में इस योजना का लाभ 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर दिया है।

(पेज-10 भी देखें)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द ही जारी होगी पंजीकरण प्रक्रिया

हम प्रत्येक भारतीय के लिए सुलभ, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, कैबिनेट ने आज 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के दायरे को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह योजना 6 करोड़ नागरिकों का सम्मान, देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रेट्र

निजी स्वास्थ्य बीमा कराने वाले भी उठा सकेंगे लाभ

अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहले से केंद्र, राज्य या किसी अन्य सरकारी विभाग की योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा पाने वाले बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान भारत के तहत इलाज का कवर पाने का विकल्प खुला होगा। ऐसे बुजुर्ग यदि चाहें तो किसी इलाज के पुराने कवर को छोड़कर आयुष्मान योजना से इलाज की सुविधा हासिल कर सकते हैं। ईएसआइसी के तहत इलाज के लिए कवर बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत के तहत कवर किए जा सकेंगे। यही नहीं, जिन बुजुर्गों ने निजी बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वैष्णव ने कहा कि फिलहाल इस योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन मांग बढ़ने पर इसमें बढ़ोतरी का विकल्प खुला रहेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- ट्रक, टेम्पो व दोपहिया पर सब्सिडी, 88,500 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन
- पीएम ग्राम सड़क योजना से बनेंगी 62,500 किमी लंबी नई सड़कें
- ईवी बढ़ाने के लिए 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना
- 2,000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम से बेहतर पूर्वानुमान और जलवायु
- जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12461 करोड़ रुपये की मंजूरी

पीएम-ई ड्राइव योजना से बढ़ेगी ईवी की संख्या

ट्रक, टेंपो और दोपहिया वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, 88,500 स्थानों पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वायु प्रदूषण से निपटने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम-ई ड्राइव नाम से एक नई योजना घोषित की है। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, टेंपो और दोपहिया वाहनों को खरीदने पर फेम-1 और फेम-2 की तरह सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही इस स्कीम के तहत देशभर के 88,500 स्थानों पर नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 62,500 किमी लंबी नई सड़कें बनाने को भी मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में बुधवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उनमें पीएम-ई-ड्राइव और ग्रामीण सड़क योजना का नया चरण शामिल है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम-ई ड्राइव के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को नए सुधार के साथ सड़कों पर उतारा जाएगा। इसमें बैटरी को पहले के मुकाबले और बेहतर बनाने पर जोर है। इस पूरी योजना पर अगले दो सालों में 10,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मौजूदा समय में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा वाहनों से ही होता है। इस पहल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी की उम्मीद है।

कैबिनेट ने इसके साथ ही दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए पीएम ग्रामीण सड़क योजना के नए चरण का एलान किया है। इसमें 62,500 किमी लंबी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना पर करीब 70 हजार करोड़ खर्च होंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अधिकतर गांव पहले ही सड़कों से जुड़ चुके हैं। कैबिनेट ने पीएम-ई-बस स्कीम को भी और आसान बनाया है, जिसमें परिवहन निगमों को बस खरीदने के लिए सरकार की गारंटी दी जाएगी।

62,500

किमी लंबी नई सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगी, योजना पर करीब 70 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मंत्रिमंडल ने बुधवार को 31,350 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए 12,461 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं को अगले आठ साल में क्रियान्वित किया जाना है। बुनियादी ढांचे की लागत को लेकर बजटीय समर्थन की सीमा को तर्कसंगत बनाया गया है। अब 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट का बजटीय समर्थन दिया जाएगा। 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ के साथ 75 लाख रुपये प्रति मेगावाट का समर्थन दिया जाएगा।

कैबिनेट ने मिशन मौसम नामक कार्यक्रम को भी मंजूरी दी

मौसम के लिए बेहतर ढंग से तैयार और जलवायु को लेकर स्मार्ट भारत बनाने के लिए मिशन मौसम नामक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। सरकार ने इसके लिए दो वर्षों में दो हजार करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के मौसम और जलवायु संबंधित विज्ञान, शोध और सेवाओं को बेहतर करना है। इसका लक्ष्य अस्थायी और स्थानिक पैमाने पर ज्यादा सटीक और समय रहते मौसम और जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए निरीक्षण और समझ में सुधार करना शामिल होगा। इसमें मानसून के पूर्वानुमान, वायु गुणवत्ता के लिए अलर्ट, मौसम में बड़े बदलाव, चक्रवात और बारिश से जुड़ी जानकारी को समझना और बेहतर ढंग से इनका उपयोग करना शामिल है।

पीएम ई-ड्राइव योजना ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और हमें एक स्थायी भविष्य बनाने में मदद करेगी। साथ ही जलविद्युत परियोजना की योजनाओं में संशोधन से दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे जल विद्युत विकास में तेजी आएगी, रोजगार सृजन होगा और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बन रही कार्ययोजना

राज्य के 8 जिलों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा

भास्कर न्यूज | मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के 5 और सीमांचल के 3 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देकर उसे उद्योग का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। बिहार विधानसभा की पर्यटन अध्ययन समिति 18-19 सितंबर को मुजफ्फरपुर, उसके बाद 27 सितंबर तक बारी-बारी से अन्य 7 जिलों में जाएगी। वहां जाकर देखेगी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहां कौन से कार्य कराए जा सकते हैं। वहां के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों को किस तरह से बचाया और उनका विकास किया जा सकता है। समिति विभाग से बात कर विलुप्त हो रही धरोहरों के उत्थान की योजना तैयार करेगी। बिहार विधानसभा के उप सचिव संजय कुमार ने इसके लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व मधेपुरा के डीएम को पत्र लिखकर इसकी तैयारी करने के लिए कहा है। इसके आलोक में डीएम सुब्रत सेन से जिले के 35 विभागों के प्रमुख को संबंधित सभी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है।

मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम व कोल्हुआ समेत कई स्थल राष्ट्रीय मानचित्र पर आएंगे

मुजफ्फरपुर जिले में बाबा गरीबनाथ धाम, सिकंदरपुर मन में बन रहा लेक फ्रंट, मणिका मन, सरैया के कोल्हुआ अशोक स्तंभ समेत अन्य पर्यटन स्थलों का विकास कर इन्हें पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की तैयारी है। वैशाली में बन रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम को भी इससे जोड़ा जाएगा। पर्यटन स्थलों के विकास के साथ सड़कों व खानपान की व्यवस्था बेहतर करने समेत पर्यटकों को लुभाने पर भी कार्य होगा। सकल घरेलू उत्पाद के तहत लहठी, लीची व अन्य उत्पादों का बाजार बढ़ाने, उत्पादन में आनेवाली समस्या-बाधाओं को दूर करने पर काम होगा। लीची की जिम्मेदारी लीची अनुसंधान केंद्र पर रहेगी।

सड़क, परिवहन, वातावरण बेहतर करने पर हो रहा काम

जिले में पर्यटकों को लुभाने के लिए सड़कों को सुंदर बनाने के साथ परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। वातावरण को संतुलित करने के लिए पर्यावरण विभाग कई स्तरों पर काम कर रहा है। इसके अलावा जिले की सभी प्रसिद्ध धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहरों को चिह्नित किया जा रहा है। धरोहरों को उद्योग से जोड़ने के लिए इनके विकास पर काम होगा। साथ ही हर जगह पहुंच का रास्ता सुगम बनाया जाएगा।

-सुब्रत सेन, डीएम, मुजफ्फरपुर

Modi sets $500bn electronics sector milestone for 2030

Agencies
letters@hindustantimes.com

GREATER NOIDA: Prime Minister Narendra Modi has set an ambitious USD 500 billion target for the country's electronics sector. At present, the electronics manufacturing sector is estimated to be about USD 150 billion, growing at a rapid pace over the past decade.

"Look at how far we have come. Today, India's electronics sector is worth more than USD 150 billion. And now our target is even bigger. By the end of this decade, we want to take our electronics sector to USD 500 billion. This will create about 6 million or 60 lakh jobs for the youth of India," PM Modi said on Wednesday, addressing the inaugural session of three-day 'Semicon India 2024' event in Greater Noida.

"Our goal is that 100 per cent of electronic manufacturing should happen in India. India will make semiconductor chips and the finished product too," PM Modi added.

The three-day conference will showcase India's semiconductor strategy and policy which envisions making India a global hub for semiconductors.

Semiconductors have grown into a crucial resource, especially as the geopolitical chasm between Beijing and Washington continues to widen and importers look to reduce their reliance on overseas producers in locations such as China and Taiwan. Several countries including the US, Germany, Japan and Singapore are investing aggressively to boost domestic chipmaking, ensuring supply of the components needed for technologies from AI to electric cars.

PM Modi explained that while industries invest and create value, the government on the other hand provides stable policies and Ease of Doing Business.

Informing that India's contribution to the world of designing is 20 percent and is growing continuously, PM Modi said that India is creating a semiconductor workforce of 85,000 technicians, engineers and R&D experts.

"India is focused on making its students and professionals industry ready", the Prime Minister remarked, recalling the first meeting of the Anusandhan National Research Foundation which aims to give new direction and energy to India's research ecosystem. He also mentioned a special research fund of ₹1 trillion.

Prime Minister Modi emphasized, "India's semiconductor ecosystem is a solution not just for India's challenges but also for global challenges."

The government has so far approved five semiconductor units in India, of which construction in two sites is on, and soon the work in the rest three will start.

India is trying to woo more chipmakers into the country, much the same way subsidies have encouraged Apple Inc. to assemble $14 billion in iPhones in the South Asian nation. Modi's administration has so far approved more than $15 billion worth of semiconductor investments. These include a proposal by conglomerate Tata Group to build the country's first major chip plant and US memory maker Micron Technology Inc.'s envisioned $2.75 billion assembly facility in Modi's home state of Gujarat. Israel's Tower Semiconductor Ltd. is seeking to partner with billionaire Gautam Adani for a $10 billion fabrication plant in western India.

In June 2023, the Union Cab-

continued on →7

PM Narendra Modi at an exhibition during the inauguration of SEMICON India 2024, in Greater Noida, on Wednesday PTI

Climate, tourism threaten to bleed out Lakshadweep's corals

Lakshadweep's ecology has been imperilled by heating seas and a string of tourism projects. HT, in a series supported by the Pulitzer Center, looks at the changes that have hit the vibrant archipelago off India's southwest coast

Jayashree Nandi and Tannu Jain

letters@hindustantimes.com

KAVARATTI: Saheer Ali, a diving instructor, first noticed mass bleaching of corals in the shallow lagoon on the western coast of Kavaratti Island in April. The whitened reefs brought on a sense of deep grief — "the kind when you see a loved one in pain".

"The ocean is our home. It gives us peace. It is also our bread and butter. It is our life," says Ali, 40, sitting outside his diving centre on a recent rainy day in September.

Scientists hope some corals will survive the mass bleaching that occurred this year but the larger question is: whether the climate crisis will spare the coral atolls that are Ali's home?

The heat stress in Lakshadweep (Laccadive Sea) and in southeastern India was record-setting in 2024, according to Derek P Manzello, Coordinator, NOAA Coral Reef Watch, Center for Satellite Applications and Research Satellite Oceanography & Climatology Division.

LAKSHADWEEP AT CROSSROADS

The metric used to gauge heat stress on corals is called Degree Heating Weeks (DHW). It shows how much heat stress has accumulated in an area over the preceding three months by adding up any temperature exceeding the bleaching threshold during that time. It is a measure of both the magnitude and duration of the thermal stress.

In 2024, Lakshadweep reached 9.2 DHWs, and southeastern India, 9 DHWs. The prior record for Lakshadweep was 6.7 DHW in 2010; it was 6.9 DHW for SE India in 2016, says Manzello.

This heat was felt by divers and fishermen who are now desperate to save the lagoon and coral reefs from damage. "The temperature of the deeper outer lagoon was 32°C but the surface water in the shallow lagoon was even warmer, around 36°C during the peak heating period in April and May. How can corals survive that heat?" asks Anwar Hussain, a Kavaratti-based fisherman.

The simple answer: They cannot

"Corals, in general, survive in temperature thresholds of 20 to 29°C. An increase of 2 degrees beyond that can negatively impact most of species, and that is what caused mass bleaching here in Lakshadweep," explains Alvin Anto, a Kochi-based researcher who focuses on corals, and the (underwater) photographer for this series.

Months later, on another dive, Anto found that a few corals were recovering. "Bleaching is over now as the monsoon has set in and temperatures have reduced marginally. However, not all corals were able to survive," he says.

To explain the phenomenon, Roxy Mathew Koll, climate scientist at Indian Institute of Tropical Meteorology, says, "This is the fever phase. Some corals can revive if cool temperatures return. As we go towards frequent marine heat waves, frequent extreme temperatures and a permanent marine heat wave state, the fever will lead to deaths, coral mortality.

"That is what we are truly scared of," says Koll, calling for "attention to coral species that actually support marine biodiversity".

Coral reefs are considered the rainforests of the sea and represent the most biodiverse ecosystem in the oceans. It is estimated that roughly 25% of all marine species associate with coral reefs at some point in their lives. Thus, the large-scale death of corals and degradation of coral reefs threatens the survival of one in four of every living organism in the ocean, Manzello explains.

"These ecosystem services include things such as coastal protection from storms and sea-level rise... many new pharmaceuticals, including experimental cancer drugs, are being developed from novel organic compounds discovered on coral reefs," he says.

Replying to a question in Lok Sabha on bleaching events in the last five years, Kirti Vardhan Singh, the junior minister for environment, said: "Coral mass bleaching is a natural phenomenon across global waters due to change in the global climate change followed by an increase in sea surface temperature... Coral bleaching events have been reported during March 2024 in Lakshadweep. During 2023, 2022, 2021 and 2020, the events of coral bleaching were not significant..."

He further called it "a sporadic event" and said "such incidents do not have a major impact on local economy such as tourism and fishermen as of now", even as he went on to list various government schemes to conserve corals.

Time is running out

But, the devastation of coral reefs in Lakshadweep is only a manifestation of how climate change is threatening the very existence of India's only coral atolls — the ring-shaped reef formations which create islands surrounded by lagoons. These islands are made of coral and coral dust as opposed to soil. Will Lakshadweep thrive, with water so clear and pristine, colourful corals and marine life?

It's difficult to say.

The Arabian Sea's character has undergone a major shift — from a relatively calm water body compared to the Bay of Bengal to a one of rather rough and unpredictable disposition in recent years. The rate of increase in sea surface temperatures over Arabian Sea is higher than that of Bay of Bengal based on data from 1982 to 2023, according to scientists at Indian Institute of Tropical Meteorology.

Meanwhile, the Centre plans to promote Lakshadweep as a major tourism destination with lagoon villas and tent cities planned in different inhabited and uninhabited islands. Lakshadweep has a land area of only 32sqkm with 10 inhabited and 26 uninhabited islands.

An aggregation of damsel fish in the thickets of a branching Acropora corals in Agatti. ALVIN ANTO

HT filed an RTI seeking information on the various tourism projects planned in the Union territory to increase tourist footfall. The response from the tourism ministry states that under Swadesh Darshan 2.0, Lakshadweep has been identified as a destination for development.

The ministry of tourism launched its flagship scheme of "Swadesh Darshan" in 2014-15 and provided financial assistance to the states, Union territories and central agencies for development of tourism infrastructure.

In another RTI, filed with the Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS), HT sought details of sea level rise around Lakshadweep islands and records of marine heatwaves. The organization, under the ministry of earth sciences, said the "information sought doesn't qualify and/or doesn't lead to any category of information as specified under the definition of 'information' defined under 2(f) of RTI ACT 2005."

The information, however, was available with climate scientists.

According to Koll, the rate of sea level rise in the Indian Ocean was recorded at about 3cm/decade during the past few decades, which is projected to increase to about 5 cm/decade. More than half of the sea level rise in the Indian Ocean is in fact due to thermal expansion of water in response to rising temperatures.

"Future climate projections from our research indicate the Indian Ocean will be in a near-permanent marine heatwave state by 2060, when global warming crosses 2°C. This can be a death knell for many coral species," he says.

"Past observations suggest sea level rise over Lakshadweep islands is around 3-5 mm per year. This is a large number. This could be impacting the atolls in the islands. With warming to continue, the sea level rise is expected to continue," says M Rajeevan, former secretary, ministry of earth sciences and climate scientists.

According to documents seen by HT on the environment ministry's Parivesh website, M/S Praveg Limited, a Gujarat-based tourism company, has sought island clearance regulation zone (ICRZ) approval for "establishment of a resort facility, encompassing accommodation, dining, recreational amenities, and associated infrastructure" in Agatti with a built-up area of 2001.5 m2.

The company, on its website, is advertising these tent resorts as appropriate for "exceptional destination weddings, corporate events, and private gathering spaces". These resorts are among the many projects being planned for the islands.

HT reached out to Praveg Ltd on August 25 and on September 5, seeking response on how many tourists the tent cities can accommodate and how these facilities comply with ICRZ 2019. There was no response from the company till the time of going to print.

Further, the Niti Ayog is planning development of eco-tourism projects on the islands with water villas and beach villas.

"I do not think lagoon villas are possible here. Reefs will completely collapse if you build these villas. Moreover, our islands do not have the capacity to support tourism. Islanders are barely managing with basics, some basic food and desalinated water. If tourists come in large numbers, the sensitive balance in the tiny islands will fail," says Ali.

There is also a worry that tourism projects are being prioritised for outsiders and will not benefit locals.

The warming Arabian Sea is also eating away at the islands. "The winds change suddenly now, and surface and underwater currents also change. It has become like the Bay of Bengal," says Hussain, the fisher from Kavaratti.

Separately, the warming has made the water acidic which further threatens the reef framework of the limestone structures built by corals and threatens the survival of marine life. "The cause is nothing but carbon. Can the people of Lakshadweep solve this problem? No. The global community has to do this to save us from disappearing," says Ali.

Lakshadweep's appeal to the world

"The projection still stands that 1.5°C global warming will see a 70 to 90% loss of coral reefs over time, a 2°C warming will lead to up to 99% loss, with regional differences. Coral species will survive in somewhat cooler pockets in deeper waters," says Hans-O Poertner, marine biologist and Intergovernmental Panel on Climate Change's Working Group II co-chair, lead author of IPCC WGII AR5, chapter 6 on Ocean Systems.

"Best protection for corals is by stopping net emissions of CO2 into the atmosphere. This is the shared responsibility of all nations according to the sum of their historical and present contributions to greenhouse gas emissions," Poertner adds.

The question is how Lakshadweep can develop in a way that doesn't harm its biggest resource — its coral reefs, unique geomorphology and culture. According to the 2011 Census, Lakshadweep has a population of 64,429 persons. More than 93% of the population are indigenous and Muslims.

"We have heard from our elders that when there was no supply of vegetables or grains from the mainland, they survived by eating coconut and fish," says Abdul Khader, former president, gram panchayat, Kavaratti (2017-2022).

Nearly everything, except coconut, some local fruits and fish, has to be shipped to Lakshadweep's islands. If cargo doesn't arrive on time, locals have to make do with what they have.

Lakshadweep is among the most developed societies in India, with an equitable, highly literate population with high levels of well-being, according to those tracking the islands for years.

It has a literacy rate of 93.71%; human development index of 0.75 compared to 0.6 for India as a whole; gender ratio of 945 females out of 1000 males; income inequality index of 21.05 compared to 35.7 for India, research by Lakshadweep Research Collective, a diverse group of ecological, social and legal researchers, has shown.

Rohan Arthur, scientist, oceans and coasts, with Nature Conservation Foundation, says that tourism is likely to be a critical element in any developmental plan for Lakshadweep. But it is important to deliberate on what kind of tourism, he insists.

"As we move towards a climate resilient future, we need to consider non-extractive ways of supporting the economy of Lakshadweep in ways that directly benefit local communities... whatever forms of development take place on these islands, they need to take into account the climate vulnerabilities of the place."

HT reached out to Lakshadweep administrator Praful Patel Khoda for an interview on the concerns facing Lakshadweep. "All your queries and interview requests have been sent to the honourable administrator's office but he is not available for an interview because of his extremely busy schedule in view of VIPs visiting the UTs," his office replied.

Congress leader Muhammed Hamdullah Sayeed, the UT's sole MP, meanwhile, said, "Lakshadweep has an extremely sensitive ecology. No project can be approved here without considering this fragility. Very robust environment impact assessment is needed for any project that is taken up here. It is important to understand that we have not contributed to this crisis so we should not be bearing the brunt."

Instability and uncertainty stalk Bangladesh

M.K. Narayanan

a former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal

It is often mentioned that the fate of individuals and nations hang by a slender thread. On August 5 this year, even as Muhammad Yunus (the current head/chief adviser of the interim government in Bangladesh) was to be arraigned before a court of law for certain alleged actions against the State, the then Prime Minister, Sheikh Hasina, was compelled to resign and flee the country to neighbouring India. This was a sequel to several weeks of protests over a 'quota system', reserving a percentage of all government jobs to descendants of 'freedom' fighters involved in Bangladesh's 'war of independence'. The government's heavy-handed measures to suppress the student demonstrations had led to a groundswell of protest against the government, and Sheikh Hasina herself. Even after the proposal for the 'quota system' was withdrawn, massive protests continued, signalling the depth of anger against the government, and Sheikh Hasina personally, compelling her to flee.

Bangladesh currently has an interim government headed by Mr. Yunus, an economist, which has the backing of the Army, and with students functioning as the 'storm-troopers'. In quick succession, the Chief Justice, the central bank governor, a host of university vice-chancellors and other key personnel were compelled to step down. The main charge levelled against Sheikh Hasina is that she had become a virtual dictator, trampling on the civil liberties of citizens and embarking on high handed actions against her political opponents.

Still early days but much can happen

It would be invidious to characterise Sheikh Hasina's ouster as a victory for 'democratic forces'. No doubt, it has some of the characteristics of the 'Prague Spring' that rocked Czechoslovakia in the mid-20th century, but the world does not have to be reminded of how the revolt was snuffed out within a short time frame. There may be no equivalent of the 'Warsaw Pact Powers' (which ended the Prague students' revolt) on the horizon in Bangladesh as of now. Today's major powers, essentially the United States and China, however, have a huge stake in how matters turn out and are not averse to meddling in Bangladesh.

What happened in Bangladesh does not conform to a classical 'colour' revolution instigated by the U.S. or the West, but it has provided scope for the 'Big Powers' to meddle in the affairs of Bangladesh, anxious to secure a base for themselves in South Asia, as part of their larger designs.

Much will depend on the turn of events. In the first flush of exuberance and anger against Sheikh Hasina, vandalism seemed to reach its apogee, with images of Sheikh Hasina and even the statue of the nation's founding father, Sheikh Mujibur Rahman, becoming targets of riotous mobs. The position of Mr. Yunus itself appears tenuous at this stage, and it is uncertain how long the Army would support the present arrangement. Pressure from political parties to hold early elections is already evident, and if and when elections are announced, it could shatter the surface calm.

The troubles in Bangladesh are by no means over and India may need new strategies to deal with the situation to its east

Areas of danger

The real concern is whether the 'democracy deficit', which Sheikh Hasina helped perpetuate to overcome political obstacles, can be offset democratically, or whether it would lead to another round of violent events. A worrying aspect is the increasing role of Islamist parties in Bangladesh which, in recent years, has become a potent force. An India intent on maintaining a balance between religion and politics would find the growing presence of radical Islamist entities a potent danger.

What India can at present possibly hope for is that the people of Bangladesh would continue to remember India's role in the early 1970s, which led to the creation of an independent state of Bangladesh. Also that any and future governments would display the same degree of warmth as the outgoing Sheikh Hasina regime. While many in India have not forgotten the 'dark days' of the early 1970s – when India had to fight a war with Pakistan on the one hand and cope with a hostile U.S. at another level, intent on detaching India from Russia – so as to bring about the independence of East Pakistan (later to become Bangladesh), India can only hope that similar sentiments still prevail in Bangladesh, notwithstanding the degree of hostility towards Sheikh Hasina and the Awami League.

For its part, India must acknowledge, and be grateful for, the support extended by Bangladesh over the years in dealing with militant groups belonging to India's northeast, that had sought sanctuary there and become a scourge for India's security establishment. Under Sheikh Hasina these militants could no longer find sanctuary in Bangladesh. A prolonged period of uncertainty in Bangladesh following recent developments could well result in the regrouping of, and revival of militant activities in India by groups such as the United Liberation Front of Asom, the Mizo National Front and the NSCN.

Meanwhile, the West, which generally views events across the globe through the prism of geo-politics, is already putting out the idea that Bangladesh might well become the crucible for the next phase of conflict between India and China. Undoubtedly, both India and China have important stakes in Bangladesh. More recently, Bangladesh has begun to make certain overtures to China to accommodate its economic and defence needs. It is quite possible that with the eclipse of Sheikh Hasina, the successor regime in Bangladesh might well seek to strengthen its China connection, even as Sheikh Hasina was seen to be manifestly pro-India. All this is, however, in the realm of conjecture, and it may be too early to view Bangladesh through the prism of geo-politics – China, India, the U.S. *et al*.

Compounding problems for India

For an India, wrestling with the problem of having to deal with difficult and uncertain situations along much of its periphery, specially to the west and the northwest, the Bangladesh developments could not have come at a worse time. In the east, it now confronts a Bangladesh that appears set to shift from being a friendly neighbour to a problem state. The vexed issue of the Rohingya Muslims, which needed an early solution, will, in all likelihood, be put on the back burner for now.

Myanmar is currently controlled by a clutch of generals (who are not above being enticed by western military advisers), and while the generals may not be overtly hostile to India at present, they do not see themselves as being in step with it. Lurking in the background are again certain external forces – not only China and Pakistan – who are likely to fish in these troubled waters. This could exert a pincer-type stranglehold on India's ambition to achieve a peaceful and prosperous South Asia.

India may, hence, need to devise a new set of strategies to deal with the emerging situation. One myth that has already been exploded is that India had little to fear from developments to its east and south. Both regions have today become highly problematic, to say the least. The threat from China also looms larger than ever before if, as is being anticipated, it could secure a beachhead in a post-Sheikh Hasina Bangladesh. A simultaneous strengthening of the China-Pakistan axis would thereafter pose a threat of a kind that had not existed for several years. More than anything else, it is the spectre of Islamist radicalism that could well haunt the entire region – more so in Bangladesh at this time alongside the threat of a possible link up between radical Islamist elements in Bangladesh, Myanmar, Thailand and Southeast Asia.

The troubles in Bangladesh are by no means over. Violent street protests are usually a precursor for events that seldom have a good ending. The experience of other countries is that students seldom achieve through protests what they seek. This has been the recent experience in Europe and elsewhere. Movements of this kind tend to be usually taken over by forces inimical to democracy. Consequently, India faces a moral and security dilemma in the wake of recent events in Bangladesh.

Cabinet approves ₹10,900-cr. scheme for e-mobility push

PM E-Drive scheme aims to enable procurement of e-buses, setting up 72,000 charging stations; plan offers subsidies or demand incentives worth ₹3,679 crore, says Ministry of Heavy Industries

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union Cabinet on Wednesday approved a scheme with an outlay of ₹10,900 crore to provide for procurement of e-buses as well as for setting up more than 72,000 charging stations for EV batteries in cities and on highways to address 'range anxiety' among buyers.

The scheme, named PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-Drive), will be valid for two years.

Charge booster

PM E-Drive scheme, approved by the Union Cabinet, aims to address range anxiety among EV buyers

- Scheme, valid for two years, will support 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, 14,028 e-buses
- ₹4,391 cr. for procurement of 14,028 e-buses by State transport undertakings of 9 cities
- ₹2,000 cr. to set up charging stations in cities with high EV penetration and on some select highways

According to a press statement from the Ministry of Heavy Industries, the scheme also offers subsidies or demand incentives worth ₹3,679 crore for e-two wheelers (e-2Ws), e-three wheelers (e-3Ws), e-ambulances, and e-trucks to buyers. The scheme will support 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-buses, the Ministry added. A total of ₹4,391 crore will be set aside under the scheme for procurement of 14,028 e-buses by state transport undertakings for 9 cities with a population of more than 40 lakh, namely Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, Surat, Bangalore, Pune and Hyderabad.

The scheme also provides for ₹2,000 crore to set up charging stations in select cities with high EV penetration and on some specified highways.